दसवीं योजना की विकास युक्ति
(THE TENTH PLAN DEVELOPMENT STRATEGY)

दसवीं योजना की विकास-युक्ति के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं :

सरकार की भूमिका की पुनर्व्याख्या
(Redefining the Role of Government)

दसवीं योजना के अनुसार, नए बदलते आर्थिक परिप्रेक्ष्य में सरकार की भूमिका की पुनर्व्याख्या करना जरूरी हो गया है। पिछले वर्षों में सरकार ने अपने ऊपर बहुत-सी जिम्मेदारियां ले रखी थीं जिससे उसकी वित्तीय तथा प्रशासनिक क्षमताओं पर अत्यधिक दबाव बन गया था और व्यक्तिगत प्रयासों व प्रेरणाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। सरकार की अत्यधिक भूमिका की आवश्यकता उन हालात में हो सकती है जब निजी क्षेत्र अविकसित हो परन्तु अब समय के साथ स्थिति काफी बदल चुकी है और भारतीय अर्थव्यवस्था में एक सक्षम व मजबूत निजी क्षेत्र जड़ पकड़ चुका है। इसलिए अब सरकारी नीतियों का रूप बदल देना चाहिए और इन नीतियों का उद्देश्य निजी क्षेत्र के लिए एक उचित आर्थिक वातावरण तैयार करना होना चाहिए।

परन्तु योजना में खासतौर पर दो क्षेत्रों की चर्चा की गई है जिनमें सरकार की अहम भूमिका बनी रहेगी : (1) सामाजिक क्षेत्र जिसमें सरकारी भूमिका को और बढ़ाना होगा; तथा (2) आधारिक संरचना (infrastructure) का विकास क्योंकि इसमें कई खामियां हैं और इन्हें भर पाना निजी क्षेत्र के बस की बात नहीं है। योजना में आधारिक संरचना को दो हिस्सों में बांटा गया है : दूरसंचार, बिजली, बन्दरगाह इत्यादि जिनमें निजी क्षेत्र को और ज्यादा अवसर प्रदान करने चाहिए; तथा ग्रामीण आधारिक संरचना एवं सड़क विकास इत्यादि जिनमें सरकार को नेतृत्व अपने हाथ में लेना होगा।

समष्टि-आर्थिक प्रबंधन व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन
(Reappraisal of Macro-Economic Management System)

आर्थिक मामलों में निजी क्षेत्र के बढ़ते महत्व के कारण तथा इसके परिणामस्वरूप व्यापार-चक्रीय परिवर्तनों के प्रति देश की

Scanned with CamScanner

बढ़ती संवेदनशीलता के कारण समष्टि-आर्थिक प्रबंधन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन करना जरूरी हो गया है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि अर्थव्यवस्था लगातार उचित व व्यवहार्य विकास पथ पर अग्रसर रहे यह जरूरी है कि मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों को और लचीला बनाया जाए। योजना के अनुसार हालांकि समय के साथ देश की मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय दर संबंधी नीति में काफी लचीलापन लाया जा चुका है तथापि राजकोषीय नीतियां पुरानी जड़ बजटीय कार्यप्रणाली (outmoded budgetary procedure) के जाल में फंसी हुई हैं। अब यह जरूरी हो गया है कि बदलते आर्थिक परिप्रेक्ष्य के अनुरूप राजकोषीय प्रबंधन व्यवस्था में उचित परिवर्तन व लचीलापन लाया जाए।

राज्य-स्तर पर लक्ष्यों की व्यवस्था
(Laying Down State-Level Targets)

भारतीय योजनाओं में अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य निर्धारित करने की व्यवस्था रही है। परन्तु राज्यों के निष्पादन में अत्यधिक अंतर देखने में आए हैं — जहाँ कुछ राज्यों में तेज विकास हुआ है वहाँ कुछ अन्य राज्य विकास की दौड़ में बहुत पीछे छूट गए हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि संवृद्धि दर में जिस तेज वृद्धि की अव व्यवस्था की गई है तथा सामाजिक सूचकों में जिस सुधार की कोशिश की गई है उनमें सफलता तभी मिल सकती है जब पिछड़े हुए राज्यों के निष्पादन में उपयुक्त सुधार हो। इस तथ्य पर जोर देने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय योजना के लक्ष्यों के साथ साथ राज्य-स्तर पर विशिष्ट लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। इससे आशा की जाती है कि राज्य स्तर पर योजना प्रणाली में नए प्राण फूंके जा सकेंगे। इस विचारधारा के पीछे निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं : (1) जिस प्रकार देश के भीतर विकास-स्तरों में व्यापक अंतर पाए जाते हैं उसी तरह विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिलों के विकास स्तरों में भी व्यापक अंतर हैं। राज्य स्तर पर लक्ष्य निर्धारित करने से राज्यों के भीतर विभिन्न जिलों के लिए बेहतर विकास परियोजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। (2) विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में विभिन्न राज्यों की सापेक्षिक स्थिति के बारे में जानकारी अपने आप से महत्वपूर्ण जानकारी होगी जो प्रत्येक राज्य को अपने विकास लक्ष्यों के प्रति सचेत करेगी और संभवतः बेहतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगी।[12]

समानता और सामाजिक न्याय के लिए युक्ति
(Strategy for Equity and Social Justice)

दसवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार यद्यपि आर्थिक संवृद्धि के गरीबी निवारण पर प्रत्यक्ष रूप से अनुकूल प्रभाव पड़ते हैं तथापि भारतीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न जड़ताओं और घर्षणों के कारण ये प्रभाव बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए समान्ता और सामाजिक न्याय के लिए सीधे व प्रभावी प्रयास करने की जरूरत है। योजना में उच्च आर्थिक संवृद्धि के साथ समानता और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित तीन-पक्षीय युक्ति अपनाने की बात की गई है :[13]

1. कृषि विकास को दसवीं योजना का मूल तत्व माना जाना चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र के विकास का ग्रामीण वर्ग पर सीधा व सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। आर्थिक सुधारों के पहले दौर में औद्योगिक अर्थव्यवस्था को लक्षित किया गया था और कृषि क्षेत्र में सुधारों को अनदेखा किया गया था। दसवीं योजना में इसे बदलने की आवश्यकता महसूस की गई।

2. दसवीं योजना की विकास युक्ति में उन क्षेत्रों का तेजी से विकास करने पर जोर दिया गया, जिनमें रोजगार प्रदान करने की ज्यादा संभावनाएं हैं और उन नीति अवरोधों का समाधान करने की बात की गई जो रोजगार बढ़ाने में रुकावट बनते हैं। खास तौर पर ऐसे क्षेत्रों के लिए नीतियां बनानी होंगी जिनमें व्यापक रोजगार संभाव्य है। ये क्षेत्र हैं – कृषि, निर्माण, पर्यटन, परिवहन, लघु उद्योग, फुटकर व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी व संचार क्षेत्र से संबंधित सेवाएं, तथा ऐसी बहुत सी नई उभर रही सेवाएं जिन्हें उपयुक्त नीतियों द्वारा प्रोत्साहित किया जा सकता है।

3. ऐसे विशिष्ट लक्षित वर्गों (special target groups) के लिए विशिष्ट कार्यक्रम व नीतियां बनाने पर जोर दिया गया है जिन्हें सामान्य आर्थिक संवृद्धि व विकास योजनाओं से या तो लाभ नहीं मिल पाता यह बहुत कम लाभ पाता है। इस तरह के कार्यक्रम हमारी विकास युक्ति का हिस्सा रहे हैं और उन्हें दसवीं योजना में भी जारी रखा गया।

12. Government of India, Planning Commission, *Tenth Five Year Plan 2002-2007*, Volume I (Delhi 2003), p. 9.
13. *Ibid.*, Box 1.3, p. 9.

Scanned with CamScanner